PROF. MADHU DANDAVATE: Is it your ruling that no privilege is involved? (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: If you want to discuss the other matters, I have no objection. You can discuss in the House. I will allow it.

PROF. MADHU DANDAVATE: Is it your ruling that no contempt is involved here?

MR. SPEAKER: You can discuss in the House. But so far as privilege is concerned that matter is over with the regret.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इसमें विवाद का सवाल नहीं है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप व्यवस्था सुने बिना कैसे आगे चलेंगे। मैं जो मुद्दा उठाऊंगा, आप उस पर निर्णय दीजिए। मैं आप की अनुमति लेकर बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, वह मेरी कन्सेन्ट में है। मैं कन्सैन्ट नहीं दे रहा हूँ।

श्री मधु लिमये : आप पहले सुन लीजिये, तभी तो निर्णय देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, उस को पढ़ने की क्या जरूरत है।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, नियम 225 इस प्रकार है :—

"The Speaker, if he gives consent under rule 222 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto."

अब मेरा प्रश्न इस प्रकार है—क्या मैंने यह साबित नहीं किया है कि सदन के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और जब सदन के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस को सदन की मानहानि, कन्टेम्प्ट कहा जाता है—मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस के अनुसार—आप पहला निर्णय इसके बारे में दीजिए।

दूसरा प्रश्न—जब आपने इस मामले को उठाने दिया तो इन्होंने माफी मांगी। मैं भी उस माफी को मान लेता, यदि यह एक टैक्निकल बात होती। जब उस से अर्थ-व्यवस्था खराब हुई है, दामों में वृद्धि हुई है तो यह कोई मामूली बात नहीं है—इसलिये आप इन दोनों मुद्दों पर निर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कन्टेम्प्ट नहीं है, मैं आप को इजाजत नहीं दूंगा। जैसा मैंने कल सुना था, वैसा ही आज सुना है, जैसे कल एपालाजी एक्सैप्ट की थी, वैसे ही आज भी की है। मैंने आपको मौका दिया है, मैंने कोई कन्सेन्ट नहीं दी है।

I am not giving my consent to it.

So far as the other matter is concerned, it is finished when he has expressed the apology.

यह दूसरा मामला भी आप का है।

MATTERS UNDER RULE 377

श्री मधु लिमये (बांका) : उठाने का फायदा ही क्या है, जब हर चीज इसी तरह से खत्म की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय दो-तीन दिन पहले पश्चिमी बंगाल के सहयोगी आन्दोलन के कुछ नेता हम लोगों के पास आये थे और उन्होंने कहा कि सहयोगिता के ऊपर पश्चिमी बंगाल की विधान सभा ने जो विधेयक पास किया है, उस विधेयक की तीन धारायें ऐसी हैं जिनके चलते स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, और गैर-सरकारी (नान-आफिशियल) सहयोगी आन्दोलन का सारी दुनिया में जो स्वरूप है, वह इन तीन धाराओं के चलते खत्म होता है। इसलिये उन्होंने हमसे प्रार्थना की कि हम लोग सदन में यह सवाल उठायें।

अब आप पूछियेगा कि यह तो राज्य का मामला है, इस सदन में कैसे उठेगा? यह

विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया है, रिज़र्व किया गया है और संविधान की धारा 200 इस प्रकार है :—

"When a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative Council, has been passed by both Houses of the Legislature of the State, it shall be presented to the Governor and the Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President ..."

अगर राज्यपाल की सम्मति तक ही सीमित रहता तो शायद यह मामला यहां नहीं उठता, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति के विचारार्थ इस मामले को आरक्षित रखा गया है, और राष्ट्रपति स्वयं अपने से तो फैसला नहीं करते, वे तो केन्द्रीय सरकार की, कैबिनेट की सलाह पर चलेंगे, इसलिये कैबिनेट हमारी बात को सुन ले। मैं केवल तीन मुद्दे संक्षेप में उठाना चाहता हूं।

इसका खंड 23 है, इसमें सरकार और रजिस्ट्रार को किसी भी चुने हुए सदस्य को सोसायटी की कार्य समिति से या जो संस्था होगी उससे निकाल देने का अधिकार दिया गया है। खंड 23, उप-खंड 11 के तहत जो हटाने का निर्णय है, उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

खंड 26 के तहत चुनी हुई मैनेजिंग कमेटी को बरखास्त करने का रजिस्ट्रार और सरकार को अधिकार दिया गया है इस निर्णय को भी किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

खंड 27 में रजिस्ट्रार और सरकार जनरल बाडी (साधारण सभा) के द्वारा जो प्रस्ताव पास किया जायगा, उस प्रस्ताव को बदलने का अधिकार इस खण्ड के तहत रखते हैं। इसलिये आपकी मार्फत जो भी सहयोगी आन्दोलन के मंत्री हैं, किसी मंत्रालय में यह मामला आयेगा। योजना मंत्रालय में जरूर आ सकता है, इसलिए उनसे मैं कहूंगा कि हमारी बातों पर विचार करें। आज न्यायालय के अधिकारों के ऊपर आक्रमण की चर्चा समूचे देश में चल पड़ी है। इन मामलों में भी यदि साधारण सदस्यों के अधिकार और कमेटियों के अधिकार आप छीन लेंगे तो उसके दो नतीजे होंगे—एक तो न्यायालय का महत्व खत्म हो जायेगा और दूसरे किसी भी सहयोगी आन्दोलन की जो स्वायत्तता और स्वतन्त्रता है और उसका जो गैर-सरकारी स्वरूप है— इस पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं— वह भी खत्म हो जायेगा। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I have also written to you in regard to this question of supersession of co-operative societies in West Bengal ...

MR. SPEAKER: What does he want to say on that?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I want to support what my hon. friend has said. The President should not give his assent to such a drastic Bill which would mean the end of the democratic functioning of co-operative societies and which would mean bureaucratisation. I do not know why the Government of West Bengal are after this.

MR. SPEAKER: Now, Shri S. A. Kader.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I had also written to you in regard to the same matter....

MR. SPEAKER: When such identical notices are received, I normally allow only one or two Members.

SHRI SAMAR GUHA: We have also got an obligation...

MR. SPEAKER: The names of the other Members are there already.

SHRI S. A. KADER (Bombay-Central South): The recent rains have damaged some of the standing crops or grains which are in the market, and reports are coming in that at Moga and other places, huge quantity of grains has been damaged.

I would like to know from Government whether the Meteorological Department had foreca t these rains, and if so, whether it was sent to the proper authorities in order to see that the grains lying in the open were covered up or were protected. Our experience of this Department is that their forecasts are generally on the wrong side; if they say that rains will come, rains will not come, and if they say that rains will not come, then rains will come. Many of us have seen the TV programmes and heard the radio programmes and seen also the newspapers, but there was no forecast about the heavy rains that had occurred. If the Meteorological Department has not forecast it, then is it an inefficient department? Or have they no implements to forecast properly? Government should look into this matter and report to the House.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Under rule 377, I want to draw the attention of Government to the news item which has appeared in the *Hindustan Standard* dated the 15th instant regarding the breakdown of one power unit in the DVC. The report says:

> "The second unit of the DVC power generating station here went out of commission and the fault is of such a serious nature that it will not be put back into commission within a fortnight, according to sources close to the plant. The unit was repaired only on May 10.... The latest trouble is likely to have an effect on the power position in Calcutta. The erratic supply has been disrupting production at the DSP and Alloy Steel Plant for the past one week."

I would also like to mention that in the month of April in the steel township of the Durgapur Steel Plant, which is under the Durgapur Steel Plant, one Bimal Chaudhury was murdered by some gangsters.

On the 6th May, again an attack had been made on a number of employees of the Durgapur Steel Plant who were connected with the Durgapur Steel Plant Employees' Union. This matter of the murder of Bimal Chaudhury was raised by the member from that constituency, Shri K. C. Halder, but nothing has come out. This repeated attack is causing serious damage to production as well as to the law and order situation in the steel township.

Another question—this is the last day and tomorrow I will not trouble you with any questions....

MR. SPEAKER: There are others waiting.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I am not allowing anything new.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Under what rule?

MR. SPEAKER: This was only about the DVC and the other matter.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Kindly sit down.

12.47 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): Shri Madhu Limaye said in the course of his speech on Appropriation No. 2 Bill, 1973 on 27th April, 1973 that:

> "वह तो आप डी० पी० यादव से पूछिये कि मैं जनता के वोट से हारा या ठप्पामारी से हारा। खुद डी० पी० यादव ने कलेक्टर के सामने कहा कि मैं ठप्पामारी से जीत गया हूं। तो मैंने कहा कि मैं कोई पेटीशन नहीं करता आप पांच साल रहिये। इस बात को काटें। कलेक्टर के सामने उन्होंने कहा है।"

Since I was not present in the House at that time, I rise to refute and contradict the unfounded allegations made by